RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था हेतु नैतिकता, सामाजिकता व संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षा नीति की आवश्यकता

डॉ. कमला

(शिक्षा शास्त्र)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 25 May 2019

Keywords
शिक्षा व्यवस्था, नैतिकता, सामाजिकता

ABSTRACT

शिक्षा नीतियां किसी भी देश के मूलभूत विकास का आधार होती हैं। शिक्षा वो जो समग्र ज्ञान के साथ आपको जीवन को बेहतर तरीके से जीने का नजरिया प्रदान करे, शिक्षा वो जो आपके विकास के साथ देश के विकास में भी सहयोगी साबित हो, वो जो एक बेहतर समाज गढ़े, वो जो एक श्रेष्ठ राष्ट्र की परिकल्पना पर भी खरी उतरे। भारत में आदर्श शिक्षा नीति का इंतजार आज तक हो रहा है क्योंकि अब तक जो भी शिक्षा नीति बनी है या उसमें संशोधन हुए हैं वो तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए उस व्यवस्था को बेहतर बनाने और सुचारु तौर पर संचालित करने की मंशा को बल देती हुई नजर आती हैं। यहां शिक्षा सुधार की गति अपेक्षित नहीं थी। यह सच है कि भारत में शिक्षा का पहला स्कूल 'घर और परिवार' होता है लेकिन मौजूदा हालात में देखें तो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवार उसकी जगह ले रहे हैं, ऐसे में शिक्षा की वो पहली पायदान ही अब अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रही है। एकल परिवार अपनी जिम्मेदारियों और भौतिक सुखों की दौड़ में शामिल हैं ऐसे में शिक्षा का घरेलू अध्याय कहीं दरक रहा है, घर के शब्द, माहौल, देखकर सीखने और सिखाने का जज्बा अब छिटक सा गया है, हम यदि शिक्षा को लेकर अब पिछड़ रहे हैं तो उसमें आरंभिक शिक्षा के खस्ता हालात और समग्र परिवारों का विघटन अहम कारण है। देश को ठोस शिक्षा नीति की आवश्यकता कल भी महसूस होती थी और आज भी हो रही है बल्कि यूं कहा जाए कि आज गहरी जरुरत में बदल गई है, लेकिन इसे समझने के लिए देश की अब तक की शिक्षा नीतियों के कुछ बिंदू देखने आवश्यक हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए कि यदि बीते सालों में समाज का नैतिक पतन हुआ है तो शिक्षा प्रणाली उस दोष से मुक्त नहीं हो सकती है, उसमें गहरे और समयानुसार ठोस बदलाव की आवश्यकता है। समाज का नैतिक पतन बताता है कि शिक्षा प्रणाली समग्र, पूर्णतः सक्षम और सभी पहलूओं को गहराई से छूने वाली नहीं रही।

वर्तमान में शिक्षा नीति आनी है और ऐसे में उम्मीदें की जानी चाहिए कि वो उन सभी पक्षों पर मजबूत होगी जहां से समाज का नैतिक विकास जुड़ा होता है। हालांकि 1952 को डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में "माध्यमिक शिक्षा आयोग" की स्थापना की गई थी, उन्ही के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन कहा गया' लेकिन इस आयोग में माध्यमिक शिक्षा के पुर्नगठन को पहले तरजीह दी गई, जबकि यहां बुनियादी शिक्षा पर भी गहराई से मंथन होता तो वर्तमान के हालात कुछ और होते, हालांकि सन् 1964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया, यहां अवश्य ही बेसिक शिक्षा पर बहुत गहराई से विचार किया गया था, हालात तब भी चिंतनीय थे और आज भी चिंतनीय हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1952 से 1964 के बीच के कालखंड में जहां शिक्षा को बुनियादी स्तर से मजबूती मिल सकती थी वह समय त्रुटिपूर्ण अथवा आंशिक शिक्षानीतियों के कारण हमें नैतिक तौर पर पीछे की ओर धकेल गया, क्योंकि 1964 में कोठारी आयोग ने अपने गहन अध्ययन के बाद जहां सुधार आवश्यक समझा वो बुनियादी शिक्षा ही थी। यह सराहनीय मंथन था।

देश की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपनी मौलिक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए थी। यह सच है कि परिस्थितियां हर कालखंड में बदलती रहती हैं, लेकिन अब तक हम जिन शिक्षा प्रणालियों के भरोसे रहे हैं वे बेशक समय की आवश्यकता को परिपूर्ण करती हों लेकिन उनमें भारतीयता, भारतीय परिवेश, भौगोलिक परिस्थितियों और भारतीय समाज के गहरे तत्वों को सहेजे रखने की मजबूती नहीं थी। सामूहिक परिवार इस देश, यहां की संस्कृति और यहां के भौगोलिक परिस्थितियों की ताकत मानी जाती थी, यहां की बुनियादी शिक्षा जो घर से ही दी जाती थी वो अव्वल दर्जे की थी और वहां से अध्ययन की दिशा में अग्रसर होने वाले बच्चे प्रबल इच्छाशक्ति वाले होते थे, लेकिन बीते वर्षों में समाज में सामूहिक परिवारों का तेजी से ह्रास हुआ हैं। परिवार टूटने लगे, बिखरने लगे और एकल परिवार उन सभी बेसिक पारिवारिक शिक्षा से दूर होते गए और हमने उसी तरह जीवन जीना सीख लिया जिस तरह शिक्षा नीति हमें बनाती गई।

...तब माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन को आवश्यक समझा गया

'स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के तीव्र गति से परिवर्तन होने के कारण उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन को आवश्यक समझा गया अतः 1948 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा की जांच करने का प्रस्ताव

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सरकार के सम्मुख रखा था। 1951 में बोर्ड ने पुनः इस भाग को दोहराया और कहा की बालक जो माध्यमिक शिक्षा पर ही अपनी भावी रूप रेखा तैयार करता है उस ओर ध्यान नही दिया जाता है। अतः भारत सरकार ने इस सुझाव को मानते हुए 25 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया। भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में "माध्यमिक शिक्षा आयोग" की स्थापना की उन्ही के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहा गया'

...सुधार मूल से आरंभ होता तो समाज और शिक्षा बेहतर होती

यहां गौर करने वाली बात यह है कि आजादी के तत्काल बाद के सामाजिक और राजनैतिक तौर पर बदलती हुई परिस्थितियों पर नजर तो रखी जा रही थी, लेकिन सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के पुर्नगठन को आवश्यक समझा गया, जबकि हमारे देश में शिक्षा की पहली पाठशाला 'घर को' ही माना गया है, लेकिन उक्त अहम बिंदू को नजरअंदाज किया गया जबकि इस विषय पर गहरा मंथन आवश्यक था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के लिए वर्ष 1951 में प्रयास आरंभ हो गए थे। हमको यह विदित होना चाहिए कि हम एक ऐसे राष्ट्र के नवनिर्माण की परिकल्पना हमेशा करते हैं जो अपनी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और कौशल के लिए विश्व में विशेष स्थान रखता है, यदि आरंभिक वर्षों में बुनियादी शिक्षा के स्वरूप पर गहन विचार विमर्श व चिंतन किया जाता तब वर्तमान शिक्षा और समाज का स्वरूप भिन्न होता। शिक्षा हमें योग्य, कर्मठ और एक नजरिये वाला श्रेष्ठ इंसान बनने में मदद करती है, शिक्षा प्रणाली इन सभी गुणों के विकास करने में पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता हमेशा से ही महसूस की गई, समग्र सुधार की परिकल्पना भी आवश्यक थी और उस पर पूरी तरह से कार्य भी होना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई चूक तो रह गई जो यह तय नहीं कर पाई कि यदि हम शिक्षा के नैतिक व सामाजिक पक्ष पर प्रबल तौर पर कार्य नहीं करेंगे तब इसके परिणाम कितने घातक रुप में सामने आ सकते हैं। यह समझा जा सकता है कि उस दौर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हालात कुछ अलग रहे होंगे, कुछ ऐसे हालात जहां से सुधार पर सीधे–सीधे और जल्द पहुंचने की छटपटाहट रही होगी, लेकिन यह भी आवश्यक था कि हम अपने देश की पुरातन शिक्षा के मूल पर पहले नजर डालते, यदि तत्कालीन शिक्षा में सुधार में शीघ्रता ही आवश्यक महसूस की जा रही थी तब बुनियादी शिक्षा से कार्य का आरंभ होना चाहिए था। सीधे अर्थों में कहा जा सकता है कि परिवार को पहली पाठशाला मानने और उसे स्वीकारने में यहां गहरा अंतर नजर आता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार मूल से आरंभ होना चाहिए था।

बुनियादी शिक्षा में सुधार की दस्तक

'शिक्षा प्रणाली में सुधार के क्रम पर हम आगे देखें तो 1952के मुदालियर कमीशन के बाद सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉ. दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उददेश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉ. कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग (1964–66) या राष्टीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिए' यहां कोठारी आयोग के गठन में और गहन समीक्षा का जो दौर था वो बुनियादी शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक माना गया, तात्कालिक परिस्थितियों में पहली बार बुनियादी शिक्षा पर कार्य के लिए बहुत गहन मंथन हो रहा था। निश्चित ही सुधार के नए प्रकल्प यहीं से निकलने चाहिए थे।

तब हम मातृभाषा की ओर लौटे

यहां पर कोठारी आयोग ने जो गहन समीक्षा की उसमें बुनियादी शिक्षा को प्रमुखता से रेखांकित किया गया, उन्होंने महसूस किया कि सुधार की शुरुआत बुनियादी शिक्षा से ही हो सकती है। कोठारी आयोग की समीक्षा के बाद जो सुझाव उनमें उन्होंने समान पाठयक्रम के जरिये बालक–बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा देने पर जोर दिया इसका सुखद पक्ष यह रहा कि समान पाठयक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने की राह बनी। इसके अलावा बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा देने के अलावा माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में भी शिक्षण को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए और 6वर्ष पूर्ण होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। कोठारी आयोग के सुझाव निश्चित ही बुनियादी शिक्षा व्यवस्था की नींव के तौर पर स्थापित हुए, उनके सुझाव ने बुनियादी शिक्षा को गहराई तक छूआ है और उससे निश्चित तौर पर बदलाव भी आया। शिक्षा में समान पाठयक्रम के कारण बालिकाओं के लिए समान अवसर बने। साथ ही मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने के सुझाव के बाद हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा के उत्थान का वह दौर था जब हम अपनी शिक्षा, अपने देश की मूल शिक्षा व्यवस्था की ओर रुख कर रहे थे। इस आयोग की समीक्षा का नतीजा रहा कि बुनियादी शिक्षा के साथ ही कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कर स्नानकोत्तर तक शिक्षा मातृभाषा में देने की राह तैयार की गई। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब वह केवल और केवल मातृभाषा ही थी जो

जल्द और गहरे तक सुधारों को पहुंचा सकती थी। मातृभाषा में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक अध्ययन का सुझाव गहरे सुधार की नींव साबित हुआ, यहां सुधार की अपेक्षित गति भी मिली।

शिक्षा नीतियों में नैतिकता, सामाजिकता तथा संस्कारों की कमी..

शिक्षा में सुधार का एक अध्याय लिखा गया था लेकिन कालांतर में उसकी गति शिथिल होती चली गई। तब से मौजूदा हालात का आंकलन किया जाए तो हम एक ऐसी पायदान पर हैं जहां हमें बार–बार यह अहसास होता है कि आखिर बीते वर्षो में शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे हालात जब नैतिक तौर पर भटकाव की स्थिति तक आ पहुंचे हैं। बात शिक्षा में नैतिकता और नैतिक शिक्षा दोनों ही आवश्यक है इस बात पर मंथन होना ही चाहिए। 1964 के कोठारी आयोग जिसमें बुनियादी शिक्षा के सुधार के कई सारे सुझाव सामने आए थे बावजूद इसके समाज की ईकाई जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करती थी उसका लगातार विघटन हुआ और वर्तमान में एकल परिवार में तब्दील हो रहे हैं। मौजूदा हालात में अब भी हम साक्षर होने के लिए ही कार्यक्रम चला रहे हैं, साक्षरता के प्रतिशत पर अब भी संतुष्ट नहीं हैं। यहां बात अध्ययन की और है और समाज के नैतिक ह्रास की और। बेशक अध्ययन में मौजूदा कालखंड नई तकनीक से लैस होकर शिक्षा के लिए विश्व समुदाय की ओर अग्रसर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा का विकास नहीं हुआ, खूब विकास हुआ है लेकिन नैतिक व सामाजिक शिक्षा वाला पक्ष हम संवार नहीं पाए। यह भी विचारणीय पक्ष है कि संयुक्त परिवारों का विघटन आखिर क्यों हुआ और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या शिक्षा प्रणाली को इससे पूरी तरह से दूर रखा जा सकता है ? शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता और सामाजिक पहलूओं को बुनियादी शिक्षा से ही अनिवार्य रुप से समझाया जाना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्यवश विगत की समस्त शिक्षा नीतियों व आयोगों द्वारा भूलवश उक्त पहलू पर मंथन नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विघटन की गति बढ़ती चली गई। वर्तमान समाज का जो स्वरुप है वह विचलित करने वाला है उच्च शिक्षित युवा अपने माता–पिता/पालक व समाज के प्रति तीव्र गति से संवेदनाशून्य हो रहे हैं इस बात का प्रमाण यह है कि उच्च शिक्षित युवाओं के शारीरिक रूप अथवा वृद्धावस्था के कारण असहाय माता–पिता अपना जीवन यापन वृद्धाश्रम में व्यतीत करने को विवश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संबंधित वर्तमान पीढ़ी शिक्षित नहीं है, शिक्षित तो है और उच्च शिक्षित है लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को नैतिकता, सामाजिकता व संस्कारों का पाठ पढ़ाने में कहीं पीछे रह गई।

मूल ही जोड़ता है और मूल ही तोड़ रहा है

पारिवारिक शिक्षा और घर की आरंभिक शिक्षा मूल है, शिक्षा का यही मूल जो कभी नैतिकता की मजबूती बना रहा क्योंकि पुरातन शिक्षा की यदि बात करें तो संयुक्त परिवार भारत का आधार होते थे, यहां एकल परिवारों का कोई आधार नहीं था। जब ये मूल जो जोड़ता था परिवार को, शिक्षा और संस्कारों को अब वो मूल जब दरकने लगा है तब वो मूल ही टूटन का कारण बन रहा है। घरों और परिवारों के विघटन के पीछे यदि शिक्षा और अशिक्षा दोनों को मान लिया जाए और दोनों की समीक्षा की जाए तब भी नीति पर सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि यदि हम शिक्षा को घर–घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अब तक साक्षरता के प्रतिशत के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं तो यकीन मानिये जो शिक्षा नीति थी उसे और अधिक बेहतर बनाया जा सकता था जिससे वे आसान और सुलभ हो सकती। दूसरा पक्ष देखें कि यदि शिक्षा के कुछ कारक ही विघटन का आधार है तो वो कौन से तत्व हैं जो हमें संयुक्त परिवार की अवधारणा से दूर होना और एकल परिवार का जीवन जीना सिखा रहे हैं, यहां स्पष्ट कहा जा सकता है नैतिक, सामाजिक व संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षा कमजोर हो गई है और वो शिक्षा जो घरों और परिवारों से आरंभ होती थी वो कहीं न कहीं परिवारों के टूटने से आहत हुई है। हमें मौजूदा हालात में देश में अब तक हुए शिक्षा नीतियों के सुधारों का आंकलन कर इस तह में पहुंचाना ही चाहिए कि आखिर वो कौन से कारक थे जो शिक्षा के बावजूद परिवारों को एकसूत्र में बांधें नही रख पाए। यहां यह कहना ही होगा कि यदि शिक्षा नैतिक मूल्यों पर प्रबल होती तब ये टूटन भी न होती। यहां एक और कारण भी स्पष्ट हो रहा है कि परिवारों के टूटने के पीछे रोजगार के संकट को भी अहम माना जा सकता था, आर्थिक तंगी के कारण परिवार टूटने के कगार तक पहुंच रहे हैं। यहां भी शिक्षा की कमजोरियां उजागर हो रही हैं क्योंकि हम अपनी शिक्षा को आधुनिक बनाने में बेशक जुटे रहे लेकिन वो रोजगार की सौ प्रतिशत गारंटी कभी नहीं बन पाई, यह प्रश्न चिंतनीय इसलिए है कि शिक्षा का मूल उददेश्य व्यक्ति को नैतिकता से, संस्कारों से, बुद्धिमता से तथा व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए लेकिन यदि शिक्षा व्यवस्था में उपरोक्त उददेश्य समाहित नहीं हैं तब शत–प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाए ये भी संभव नहीं है। आजीविका उपार्जन करने के लिए रोजगार का होना किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है अन्यथा की स्थिति में आर्थिक संकट ही परिवारों के टूटने का कारण बनता है तब भी यहां कहा जा जाएगा कि न तो हममें नैतिकता वाली सहनशीलता का संचरण हुआ और न ही रोजगार को लेकर हम कभी भी आश्वस्त हो पाए।

चुनौतियां और उम्मीदें साथ–साथ

वर्तमान दौर में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि वो विकराल समस्या बनती जा रही है, उसका हल खोजना बहुत

दिन प्रतिदिन चुनौती होता जा रहा है। आधुनिकीकरण के इस दौर में नई शिक्षा नीति का सभी को इंतजार है लेकिन उस शिक्षा नीति के सामने उम्मीदों के साथ और चुनौतियों का भी अंबार लगा हुआ है। यह भी सच है कि नई शिक्षा नीति पर ही देश और देश की भावी पीढ़ी का भविष्य निर्भर करेगा कि वो कौन सी दिशा पाएगा। यहां अब तक की शिक्षा नीतियों और आयोगों के सुझाव के बाद अब जबकि नई शिक्षा नीति आने को है तब यह भी बहुत स्पष्ट कहा जा सकता है कि शिक्षा की कमियों और उनके सुधारों का आकलन अब मुश्किल कार्य नहीं है। अब तक के आयोगों के सुझावों के साथ ही जो इतना समय बीता है उसमें काफी कुछ बदलाव आया है, शिक्षा का चेहरा बदल गया है, सुविधाएं पहले से अधिक हो गई हैं, शिक्षा के लिए स्कूलों की दूरी भी अब बड़ा मुददा नहीं है क्योंकि स्कूल सुगमता से मौजूद हैं लेकिन चुनौती यह है कि शिक्षा व्यवस्था के पाठयक्रमों में नैतिकता, सामाजिकता, संस्कारों व राष्ट्रहितैषी जैसे मूल तत्वों का समावेश कैसे किया जाए। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई नीति के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि ये नीति वो नीति साबित होगी जो देश में अब तक आदर्श शिक्षा नीति के लंबे इंतजार को विराम दे देगी।

देश के विकास हेतु नई शिक्षा नीति में नैतिकता, सामाजिकता व संस्कारों का समावेश जरुरी

शिक्षा जीवन में बेहतर बनाती है लेकिन नैतिक शिक्षा आपको विनम्र और व्यवहारिक बनाती है। 'नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। भारत की पुरातन शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि इसके नागरिक किस स्तर के हैं और यह स्तर वहां की शिक्षा–पद्धति पर निर्भर रहता है। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊंची उठ सकी थी' यहां यदि हम इस पूरे आलेख के सार को समझना चाहें तो बहुत ही स्पष्टता से ये स्वीकार करना ही होगा कि जब तक हम अपनी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का मूल्य गहरे तक नहीं पढ़ाएंगे, गहरे तक नहीं समझाएंगे तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। नैतिक शिक्षा के बिना सफलता तो हासिल की जा सकती है लेकिन वो सफलता सुखद अहसास वाली नहीं होगी, वो आपका सामाजिक तौर पर किसी बहुत गहरे चिंतक या सुधारक के तौर पर स्थापित नहीं कर पाएगी। मेरा विचार है कि शिक्षा में नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिकता व संस्कारों से परिपूर्ण पाठयक्रम को बुनियादी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अनिवार्य हिस्सा बना दिया जाए। इससे न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, समाज को मजबूती मिलेगी और संयुक्त परिवारों का विघटन भी थम जाएगा।

संदर्भ

1. मुदलियार आयोग के सुझाव
2. कोठारी आयोग के सुझाव
3. आओ देश गढ़ें (आदर्श शिक्षा नीति और मेरे सुझाव – बालादत्त शर्मा)
4. विकिपीडिया से साभार 'नैतिक शिक्षा'
5. विकिपीडिया से साभार, 'अब तक की शिक्षा नीतियों का विवरण'
6. वेबपोर्टल जिज्ञासा से 'गुणवत्ता शिक्षा' से संदर्भ

RRIJM 2015, All Rights Reserved